Useful For Prelims

Date: 18 January 2026

गुवाहाटी के सरुसजाइ अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्टेडियम में बागुरुंबा द्वौ 2026 कार्यक्रम के तहत पारंपरिक बोडो नृत्य बागुरुंबा की प्रस्तुति देते लोक कलाकार .

गुवाहाटी : 10,000 कलाकारों का बागुरुंबा, पीएम बने साक्षी

बागुरुंबा द्वौ 2026

एजेंसियां, गुवाहाटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां बोडो समुदाय का पारंपरिक बागुरुंबा नृत्य देखा. इस नृत्य कार्यक्रम में 10,000 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया. दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम बोडो संस्कृति का जश्न है और समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. इसके पहले पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया.

23 जिलों के 81 विस क्षेत्रों से आये कलाकार : बागुरुंबा द्वौ 2026 नामक यह प्रस्तुति सरुसजाइ क्षेत्र में अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्टेडियम में हुई. कार्यक्रम में 23 जिलों के 81 विधानसभा क्षेत्रों से आये लगभग 8,000 नर्तकों सहित 10,000 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया. असम के बोडो समुदाय का लोक नृत्य बागुरुंबा की जड़ें प्रकृति में गहराई से निहित है. यह खिलते फूलों व मानव जीवन और प्राकृतिक दुनिया में सामंजस्य का प्रतीक है.

कांग्रेस ने किया असम का असम्मान : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर असम की संस्कृति और विरासत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि घुसपैठियों के लिए पार्टी द्वारा लाल कालीन बिछाने से यह स्पष्ट हो गया है. मोदी ने यह भी दावा किया कि भाजपा सरकार पिछली कांग्रेस सरकारों के पापों को धो रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि असम का बोडोलैंड मुख्यधारा से कटा रहे. बागुरुंबा द्वौ नृत्य उत्सव ही नहीं है, बल्कि बोडो समुदाय के प्रति सम्मान का प्रतीक है.

चूल्हे की आंच से नहीं, अपने निर्णय के ताप से पहचानी जाती हैं

उत्तर भारत की सशक्त महिलाएं

उत्तर भारत की महिलाओं को लेकर जब कोई वक्तव्य उन्हें रसोई की आग, बच्चों की परवरिश और घरेलू दायरों तक समेट देने की कोशिश करता है, तब वह केवल शब्दों का नहीं, बल्कि यथार्थ का भी अपमान करता है। सच्चाई यह है कि उत्तर भारत की महिला आज चूल्हे की आंच से नहीं, अपने निर्णय के ताप से पहचानी जाती है। उसने शिक्षा को केवल डिग्री नहीं, बल्कि दृष्टि बनाया है। परिवार को बोझ नहीं, आधार समझा है और अवसर को प्रतीक्षा का विषय नहीं, कर्म का निमंत्रण माना है। वह घर संभालते हुए भी उद्योग खड़ा कर रही है। समाज से जुड़ते हुए भी नेतृत्व निभा रही है। वह बिना शोर किए अपने काम से उन सभी धारणाओं को झूठा सिद्ध करती है, जो उन्हें कमतर आंकने का साहस करती है।

रविवार विशेष

Sci & Tech

भास्कर इंटरव्यू जोहो के फाउंडर वेम्बू कहते हैं- करिअर सिर्फ डिग्री से नहीं, स्किल से बनेगा; AI अपनाएं, गुलाम न बनें

AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का समय ताकि विदेशी निर्भरता घटे

संचित श्रीवास्तव
तेनकासी (तमिलनाडु) से

भारत में इन दिनों 'मेड इन इंडिया' टेक पर बहस छिड़ी हुई है। सरकार के कई मंत्रालय भी गूगल-माइक्रोसॉफ्ट छोड़ जोहो के वर्कस्पेस पर शिफ्ट हो चुके हैं। एआई जैसी तकनीक में भारत के भविष्य पर जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू कहते हैं, गूगल ने एआई में 15 साल तक निवेश किया। रिसर्च हुई, पेपर पब्लिश हुए, प्रयोग हुए। ओपनएआई जैसी कंपनी भी उसी रिसर्च इकोसिस्टम से निकली। सीख है कि अब हम भी एआई के क्षेत्र में रिसर्च-इनोवेशन पर 10 साल का 'टेक रेजिलिएंस' प्लान बनाएं। अगर हमें बाजार से फल नहीं खरीदने तो खुद के पेड़ लगाने होंगे। शायद 1-2 साल में नतीजे न दिखें, पर 5-10 साल में रिटर्न आएगा, वही असली निवेश होता है।

स्टीव जॉब्स ने कहा था, कम्प्यूटर इंसानी दिमाग के लिए साइकिल की तरह है... मैं एआई को भी इसी तरह देखता हूं।

10 साल का रोडमैप AI आज फैशन है पर मेटलर्जी से सेमीकंडक्टर्स तक सभी में फोकस जरूरी

▪ भारत सरकार के कई मंत्रालय विदेशी कंपनियां छोड़ जोहो पर शिफ्ट हो रहे, क्या यह स्वदेशी टेक में एक माइलस्टोन है?
यह एक माइलस्टोन जरूर है, पर रास्ता अभी लंबा है। टेक्नोलॉजी में हमारी बाहरी निर्भरता बहुत ज्यादा है। एआई का उदाहरण लीजिए। हमें एआई के लिए एनवीडिया की जीपीयू चिप्स चाहिए होती हैं। कम लोग जानते हैं कि पूरे भारत को साल भर में सिर्फ 50 हजार जीपीयू चिप्स का कोटा मिलता है, जबकि ओपनएआई या ग्रोक जैसी कंपनियों के पास लाखों चिप्स हैं, यानी पैसा होने के बावजूद हम उन्हें खरीद नहीं सकते। हमें अब ये सभी तकनीकें घर पर विकसित करनी होंगी। सिर्फ AI पर अटकना गलती होगी। AI आज फैशन है, लेकिन देश को 100-200 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पहचाननी होंगी, मेटलर्जी से सेमीकंडक्टर्स तक, सभी क्षेत्र में फोकस जरूरी है।

वर्क-लाइफ बैलेंस की डिबेट पर आपकी क्या राय है?
जहां सोच और रचनात्मकता अहम है, वहां काम किसी तय समय-सीमा में बंधा नहीं होता। कई बार मैं जब वॉक करता हूं तो समस्या के बारे में सोचता हूं। कह सकते हैं कि मैं चलते-फिरते भी काम करता हूं, लेकिन कुछ नौकरियों में वर्क-लाइफ बैलेंस जरूरी हैं, जैसे सर्जन या पायलट। अगर वे थके हुए हों और गलती कर दें, तो उसकी कीमत किसी की जान हो सकती है। इसलिए ऐसे पेशों में काम और आराम के बीच स्पष्ट सीमा जरूरी है।

▪ आपने '10 साल की टेक रेज़िलिएंस' की बात की, वो क्या है?
मैं अक्सर कहता हूं कि हम नेलकटर तक नहीं बनाते। आप बाजार से नेलकटर खरीदेंगे, तो वह चीन, कोरिया या जापान में बना होगा। कोरिया हमसे ज्यादा समृद्ध इसलिए है क्योंकि वह छोटे-छोटे प्रोडक्ट भी बनाता और बेचता है। अगर हमें ग्लोबल प्लेयर बनना है, तो 10 साल की नीति बनानी होगी। आलोचना सहनी भी सीखनी होगी। 20-25 साल पहले चीनी स्टार्टअप्स की भी खूब आलोचना होती थी, कहा जाता था, घटिया हैं, नकल करते हैं। आज चीन तकनीक में कहां हैं... हम जानते हैं।

▪ एआई के दौर में युवाओं का फोकस क्या हो, डिग्री या स्किल?
स्किल पर फोकस हो। मैं यह नहीं कहता कि छात्र तुरंत कॉलेज छोड़ दें। लेकिन डिग्री के साथ-साथ अपनी फील्ड से जुड़ी नई-नई स्किल्स जरूर सीखें। अगर आप इंजीनियर हैं, तो कुछ बनाइए। शुरुआत में कोई भले समस्या हो... लेकिन करते रहिए।

▪ क्या एआई नौकरियां छीन लेगा?
आज स्विट्जरलैंड के एक टीचर को आईफोन खरीदने के लिए 3 दिन काम करना पड़ता है। भारत में वही आईफोन खरीदने के लिए टीचर को 3-6 महीने लग सकते हैं। तो क्या कोई टीचर इस बात को लेकर दुखी होगा कि कम काम करके वो आईफोन खरीद पा रहा है? एआई से दरअसल हमारी गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, लेकिन नौकरियों का नेचर बदलेगा। तकनीक सस्ती होगी और जो सामान्य काम हैं, उनकी जगह स्पेशिलाइज्ड जॉब्स विकसित होंगी। अर्थव्यवस्था मशीनों की नहीं होती। मशीनें उपभोक्ता नहीं हैं। इकॉनमी इंसानों से चलती है।

-शेष इंटरव्यू पढ़ें पेज 13 पर

पूरा वीडियो इंटरव्यू देखने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें

संडे एंकर आमतौर पर मई-जून में गंडक नदी में ऐसे हालात होते हैं, लेकिन छह माह पहले ही यह हाल है

जनवरी में ही सूखी गंडक, 100 मीटर में सिमटी मुख्य धारा

गोपालगंज | सालों भर अविरल प्रवाह वाली गंडक नदी इस वर्ष जनवरी में ही सूख गई। नदी की तलहटी 90% फीसदी सूख गई है। आमतौर पर मई-जून में ऐसे हालात होते हैं, लेकिन छह माह पहले ही यह हाल है। करीब डेढ़ किलोमीटर चौड़ाई में बहने वाली गंडक की मुख्य धारा सिमटकर महज 100 मीटर रह गई है। लोग बताते हैं कि गंडक नदी की ऐसी स्थिति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी।

भास्कर एक्सपर्ट

महेन्द्र महिला कॉलेज के प्रो. पंकज कुमार के अनुसार बारिश की कमी और वर्षों से जमा हो रही गाद से नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है। कमला राय कॉलेज की व्याख्याता डॉ. अंजली श्रीवास्तव का मानना है कि गंडक की तलहटी में जमा मोटी गाद व रेत ने जलधारण क्षमता को कम कर दिया है। इससे पानी फैलने की जगह नहीं मिलती।

'पर्यावरण बचाने की मुहिम में जनभागीदारी जरूरी'

साक्षात्कार

रुमनी घोष ● जागरण

- 'चैंपियंस आफ द अर्थ' पुरस्कार से सम्मानित आइएएस सुप्रिया साहू ने 23 वर्ष पूर्व शुरू किया था अभियान
- प्लास्टिक चेक पोस्ट, पीले कपड़े का बैग, खास तरह का पेंट और 100 नए जंगलों के जरिये जारी है लड़ाई

नई दिल्ली: नए साल में देश को जिन बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ेगा, उनमें जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और घटती हरियाली अहम हैं। उत्तर में अरावली से लेकर सुदूर दक्षिण के जंगलों तक 'तबाही' के निशान फैले हैं। इन निशानों को मिटाकर नए सिरे से पर्यावरण सुधार की परिभाषा गढ़ने में जुटे चुनिंदा चेहरों में एक हैं आइएएस सुप्रिया साहू। वर्तमान में तमिलनाडु सरकार में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। हाल ही में उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 'चैंपियंस आफ द अर्थ' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उनका कहना है कि पर्यावरण बचाने की मुहिम 'सरकारी' होगी तो बंद हो जाएगी। इसमें जनभागीदारी जरूरी है। सुप्रिया बताती हैं कि 23 साल पहले नीलगिरि के जंगलों में जंगली हाथियों व भालुओं को पालिथिन खाते देखकर उद्वेलित होने के बाद स्थानीय रहवासियों की मदद से पर्यावरण बचाने की मुहिम छेड़ी। दो साल तक कई प्रयोग करने के बाद जनभागीदारी का माडल तैयार किया। अहम था, वारलियार के पास प्लास्टिक चेक पोस्ट बनाना। चेकपोस्ट से गुजरने वाली गाड़ी से प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर री-साइकिल के लिए भेज दी जाती है। पिछले साल जब्त प्लास्टिक से 11 किमी सड़क बनाई गई।

आइएएस सुप्रिया साहू ● जागरण

इन नवाचारों की हुई अंतरराष्ट्रीय मंच पर गूंज

- तमिलनाडु के 38 में से 14 जिले समुद्री तट पर स्थित हैं। इन्हें समुद्री आपदाओं से बचाने के लिए 2400 हेक्टेयर में नए मैंग्रोव का प्लांटेशन किया गया, जबकि 1200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मैंग्रोव रिस्टोरेशन किया गया।
- प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए 200 कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीनों को मंजपई वेंडिंग मशीन में बदल दिया गया। 10 रुपये डालते ही बैग मिल जाता है।
- 'बीट द हीट' अभियान के तहत 300 सरकारी स्कूलों की छतों पर 'सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट' किया गया है, जिससे गर्मी के दिनों में तापमान पांच डिग्री तक कम हो जाता है।

पूरा साक्षात्कार पढ़ने के लिए स्कैन करें।

टेक्नो-फेस्ट • आईआईटी खड़गपुर में इसरो निदेशक

इसरो अब 60-80% तक इनपुट स्टार्टअप से ले रहा है: नारायणन

उन्नति झाबक | खड़गपुर

इसरो के चेयरमैन डॉ. वी नारायणन ने शनिवार को कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र अब स्टार्टअप, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी पूरी तरह खुल चुका है। यहां तक कि इसरो अपने कई मिशन और प्रोजेक्ट्स में 60-80% का इनपुट (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर) स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों से सहयोग से लेता है। आईआईटी खड़गपुर के टेक्नो-फेस्ट 'क्षितिज' में नारायणन ने कहा, 'कोविड के समय देश में सिर्फ तीन स्पेस स्टार्टअप थे। लेकिन, महज 5 साल में इनकी संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है। स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए छात्रों के पास अब इसरो एकमात्र विकल्प नहीं है।'

2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन तैयार होगा

इसरो चेयरमैन ने बताया कि अभी पृथ्वी की कक्षा में 56 सैटेलाइट हैं, जो संचार, नेविगेशन, मौसम और सुरक्षा जैसी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2026 में मानवरहित मिशन होंगे। 2035 तक पूरा भारतीय स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा।

आईआईटी बॉम्बे की खोज • स्वेटर, हीटर पर निर्भरता कर सकती है खत्म

सूरज की रोशनी से चार्ज होगी थर्मल बैटरी... तेज ठंड में भी देगी गर्माहट

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

ठंड से बचने के लिए भारी जैकेट, स्वेटर और बिजली से चलने वाले हीटर पर निर्भरता बीती बात हो सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे और तिरुअनंतपुरम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक पहनने योग्य, हल्की और कपड़े जैसी 'थर्मल बैटरी' विकसित की है। यह थर्मल बैटरी सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर इसे ऊष्मा के रूप में संग्रहित करती है, बाद में यह अंधेरे या ठंड में धीरे-धीरे गर्मी छोड़ती है।

कैसे काम करती है तकनीक: यह तकनीक बिना किसी इलेक्ट्रिक तार, बिजली या भारी उपकरण के काम करती है। पारंपरिक बैटरियों के विपरीत, इसमें रासायनिक से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता, इलेक्ट्रोड या वायरिंग की जरूरत नहीं होती। इससे इसकी दक्षता बेहतर होती है और यह कई चार्ज-डिस्चार्ज चक्रों में स्थिर रहती है।

सूर्य की गर्मी को कैद करने वाला स्मार्ट पॉलिमर

- **विशेष पॉलिमर बनाया**: शोध में वैज्ञानिकों ने पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल (पीईजी) और पॉलीस्टाइरीन को-एलाइल अल्कोहल (पीएसएए) की वैकल्पिक शृंखलाओं को जोड़कर एक विशेष पॉलिमर बनाया।
- **क्या खास**: पीईजी लचीला होता है और ऊष्मा संग्रहण की क्षमता रखता है, जबकि पीएसएए संरचनात्मक मजबूती देता है। तापमान बढ़ने पर पीईजी के हिस्से 'चयनात्मक रूप से पिघलते' हैं, लेकिन पूरा पदार्थ ठोस ही बना रहता है।
- **कैसे संभव**: पॉलिमर मैट्रिक्स में ग्राफीन ऑक्साइड मिलाने से सीधे सौर ऊर्जा से ऊष्मा में रूपांतरण संभव हुआ।

BIHAR

Dainik Jagaran Page

Hindustan Page

विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग • कैथवलिया में 7 तीर्थों के पवित्र जल से अभिषेक और हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा के बीच शिवलिंग को गर्भगृह में किया गया स्थापित

विराट मंदिर में विराजे शिव

भास्कर न्यूज | कैथवलिया

कैथवलिया में शनिवार को सनातन परंपरा का ऐतिहासिक क्षण साकार हुआ। विराट रामायण मंदिर के गर्भगृह में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग (33 फीट) की स्थापना की गई। आगम व वैदिक विधि से 21 विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच महादेव विराजमान हुए। हर-हर महादेव और जय श्रीराम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भोपाल से आए दो बड़े क्रेन की मदद से शिवलिंग को स्थापित किया गया। इससे पहले काशी, अयोध्या और पटना हनुमान मंदिर के पंडितों ने विभिन्न नदियों से लाए गए पवित्र जल से अभिषेक कराया। 64 देवताओं की बेदी पूजा, 1008 शिवलिंग का आह्वान और महाबलीपुरम से आए तांबे व सोने के यंत्र की विधिवत पूजा के बाद सहस्त्रलिंगम को स्थापित किया गया। पूरी प्रक्रिया करीब 20 मिनट में संपन्न हुई।

इस ऐतिहासिक पल के साक्षी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार चौधरी बने। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे हेलिकॉप्टर से पहुंचे और शिवलिंग का दर्शन किया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मंदिर निर्माण और शिवलिंग की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पूजा मंडप में फूल अर्पित कर बिहार की उन्नति की कामना की। डीजीपी विनय कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

सीएम ने फूल अर्पित कर बिहार की उन्नति की कामना की

मंदिर...

ऊंचाई	270 फीट
चौड़ाई	540 फीट
लंबाई	1080 फीट
क्षेत्रफल	120 एकड़
मंदिर	22
शिखर	12

सबसे ऊंचा शिखर- 270 फीट

शिवलिंग...

ऊंचाई	33 फीट
गोलाई	33 फीट
वजन	210 एमटी

2 बड़े क्रेन भोपाल से आए। उनकी मदद से शिवलिंग को मंदिर के पीठ पर स्थापित किया गया।

7 नदियों का पवित्र जल, 500 संत

कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री का जल यज्ञशाला में रखा गया। अयोध्या के राजकुमार अपनी टीम के साथ सरयू का जल लेकर पहुंचे। 500 से अधिक साधु-संत इस मौके पर मौजूद रहे।

शांभवी व सायन मुख्य यजमान

पूजा में मंदिर संस्थापक स्व. किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल और पुत्रवधू, सांसद शांभवी चौधरी मुख्य यजमान बने। आचार्य भवनाथ झा के नेतृत्व में पूजा संपन्न हुई।

भास्कर नॉलेज

- विराट रामायण मंदिर क्यों खास है?
  -निर्माण पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा और अंकोरवाट से भी विशाल माना जाएगा।
- गिनीज बुक में दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है?
  -बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड मंदिर के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद बाद गिनीज बुक को अनुशंसा भेजेगा।
- गर्भगृह की क्षमता कितनी होगी?
  -गर्भगृह में 10 हजार श्रद्धालु जलाभिषेक कर सकेंगे।

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट

मंत्रोच्चार से गूंजा कैथवलिया

कैथवलिया से धनंजय मिश्र

शनिवार को कैथवलिया गांव में जश्न का माहौल रहा। सुबह 5 बजे से मंगल गीत गूंजने लगे। महिलाएं, पुरुष और बच्चे मंदिर की ओर बढ़ते दिखे। सुबह 8 बजे यज्ञ मंडप में पूजा शुरू हुई। मंत्रोच्चार की ध्वनि 20 किमी तक सुनाई दी। कई जगह लाइव प्रसारण हुआ। 10 बजे क्रेन से शिवलिंग उठाया गया। 11:50 बजे मुख्य सचिव और डीजीपी का हेलिकॉप्टर उतरा। 12 बजे मुख्यमंत्री पहुंचे। दोपहर 3 बजे हेलिकॉप्टर से शिवलिंग पर पुष्पवर्षा हुई।

बिहार में रोजगार के लिए उद्योग और डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना

संवाददाता, पटना

समृद्धि यात्रा में बोले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है और अब एक करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य है. इसके लिए राज्य में उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है. उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में देश की सबसे अच्छी उद्योग नीति बनायी गयी है. बिहार में उद्योग कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसके साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जायेगा. मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन पूर्वी चंपारण में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बातें कही. श्री चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का काम किया है. 2005 से पहले यहां सड़कें, बिजली, साफ पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब थी. पटना से मोतिहारी आने में सात से आठ घंटे लगते थे, लेकिन आज यह दूरी चार घंटे में तय हो रही है. बिहार में अब एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाया जा रहा है. रक्सौल में एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है. मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि 2005 से पहले शहरों में बमुश्किल चार से पांच घंटे ही बिजली मिलती थी, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार के हर गांव और शहर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है. अब तो सरकार द्वारा एक करोड़ 90 लाख परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है. श्री चौधरी ने कहा कि पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा सहस्त्र लिंगम स्थापित किया गया है. सरकार इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए चाहरदीवारी, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करायेगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए जनता ने जो जनादेश दिया है, उसके लिए सरकार आभारी है. मोतिहारी की जनता ने यहां 11 में से 10 सीटों पर एनडीए को आशीर्वाद दिया है. श्री चौधरी ने कहा सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी. कहा कि अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर, मोतिहारी में विराट रामायण मंदिर निर्माण के बाद अब सीतामढ़ी के पुनौराधाम में मां जानकी की जन्मस्थली पर भव्य जानकी मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है. मोतिहारी में विराट रामायण मंदिर निर्माण के बाद अब सीतामढ़ी के पुनौराधाम में मां जानकी की जन्मस्थली पर भव्य जानकी मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है.

नीरा अब बिना केमिकल के छह महीने तक रह सकेगा ताजा

मनोज कुमार, पटना

- वैज्ञानिकों ने शोध में परीक्षण कर निकाली नयी तरकीब, रिसर्च पेटेंट कराने की तैयारी शुरू

खजूर और ताड़ से निकलने वाला पौष्टिक पेय नीरा अब छह माह तक ताजा रहेगा. बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) सबौर के वैज्ञानिकों ने इस पर दोबारा शोध शुरू किया है. बिना किसी केमिकल पदार्थ के मिलावट से नीरा को कमरे के तापमान पर छह महीने तक सुरक्षित रखा जा सकेगा. इसकी पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है. नीरा संरक्षण की इस तकनीक का प्रदर्शन व प्रशिक्षण बिहार के 38 जिलों में किसानों, उद्यमियों और जीविका कैडर को दिया गया है. यह तकनीक किसानों और उद्यमियों के लिए आमदनी का नया रास्ता खोलेगी.

केमिकल युक्त नीरा 10 दिनों तक ही सुरक्षित रह सका : प्रयोग के तौर पर चूने की परत चढ़े मिट्टी के बर्तन को शाम में खजूर के पेड़ पर टांगा गया. सुबह सूर्योदय से पहले नीरा निकाला गया. संग्रहित नीरा को कोल्ड चेन के माध्यम से प्रयोगशाला लाया गया और विभिन्न प्रसंस्करण विधियों से गुजारते हुए अलग-अलग पैकेजिंग सामग्री में भरकर आगे की जांच की गयी. इसे कमरे के तापमान और शीत भंडारण दोनों स्थितियों में रखा गया. नियमित अवलोकन एवं रासायनिक विश्लेषण किये गये.

कोविड के कारण बंद हो गया था शोध, बीएयू ने दोबारा शुरू किया

वर्ष 2018-19 में नीरा संरक्षण को लेकर शोध शुरू हुआ था. वर्ष 2020-21 में कोविड के कारण इस प्रयोग में बाधा आयी और इसे फिर आगे बंद कर दिया गया था. इस पर शोध करने के लिए उद्योग विभाग ने बीएयू को 25 लाख रुपये भी दिये थे. शोध कार्य बंद होने के बाद बीएयू ने लगभग 15 लाख रुपये उद्योग विभाग को लौटा दिये थे. इसके बाद दोबारा वर्ष 2023 में बीएयू ने इस पर दोबारा शोध किया. इस पर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय ने 15 लाख रुपये दिये. 2023 में प्रयोगशाला स्तर पर कार्य पूर्ण हुआ और 2024 में औद्योगिक स्तर पर ले जाया गया. अब 2025 में इसे लॉन्च किया गया.

बिहार में शराबबंदी से घटी पारिवारिक कलह

जागरण संवाददाता, कानपुर : बिहार में 10 वर्ष पहले की गई शराबबंदी के फायदे दिखने लगे हैं। आइआइटी-कानपुर के एक शोध के अनुसार शराबबंदी के बाद लोग शराब की जगह खान-पान पर ज्यादा धन खर्च कर रहे हैं। पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन और हेल्दी फैट मिल रहा है। साथ ही प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (प्रोसेस्ड फूड) के इस्तेमाल में कमी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं और घरेलू कलह कम हुई है।

नीतीश कुमार की सरकार ने एक अप्रैल, 2016 को शराबबंदी का आदेश लागू किया था। आइआइटी-कानपुर के आर्थिक विज्ञान विभाग के विनायक कृष्णात्री के अनुसार, इस प्रतिबंध से न सिर्फ घरेलू संसाधन बचे, बल्कि सकारात्मक व्यवहार में भी बदलाव आया है। शराब का सेवन घटने से वैवाहिक कलह कम हुई। घरेलू स्थिरता में सुधार हुआ और पौष्टिक भोजन पर खर्च को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा फायदे देखे गए, जहां प्रतिबंध का प्रवर्तन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है। नीति-संबंधी निष्कर्ष यह है कि एक ऐसे राज्य में प्रोटीन के सेवन में वृद्धि हुई है, जहां पारंपरिक रूप से आहार में अनाज का प्रभुत्व है। सस्ते, अस्वास्थ्यकर फैट से हटकर बेहतर गुणवत्ता वाले खाना पकाने के तेलों की ओर झुकाव हुआ, जिससे समग्र आहार गुणवत्ता में सुधार हुआ। दालों, डेरी उत्पादों और नट्स से बने तेल और अन्य खाद्य स्रोतों से कैलोरी, प्रोटीन और फैट का सेवन काफी बढ़ गया है। पैकेटबंद सामान की खपत में कमी आई, जो अक्सर शराब के साथ उपयोग किए जाते हैं।

- पौष्टिक भोजन पर ज्यादा खर्च कर रहे लोग, आइआइटी-कानपुर के शोध में निकला यह निष्कर्ष
- एक अप्रैल, 2016 को शराबबंदी का आदेश लागू किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने

बिहार में शराबबंदी का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा और शराब से संबंधित सामाजिक नुकसान को कम करना था। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि इससे पोषण और स्वास्थ्य लाभ भी हुए। खर्च को शराब से खाने की चीजों पर शिफ्ट करके डाइट की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ।
-सुकुमार वेल्लाक्कल, प्रोफेसर, आर्थिक विज्ञान विभाग

शोध में बिहार की तुलना उप्र, झारखंड व बंगाल से

आइआइटी-कानपुर का शोध पत्र एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोध करने वाली टीम ने नेशनल सैंपल सर्वे आफिस (एनएसएसओ) द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के दो राउंड (2011-12 और 2022-23) के घरेलू स्तर के डाटा के आधार पर विश्लेषण किया। व्यापक समय के रुझान और क्षेत्रीय आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए शोधकर्ताओं ने पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से बिहार की तुलना की। निष्कर्षों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए कई सांख्यिकीय मिलान तकनीकों का उपयोग किया।

***

भास्कर एक्सक्लूसिव बिहार के 71 हजार स्कूलों में पढ़ने वाले 1.09 करोड़ छात्रों को दोपहर में भोजन दिया जाता है

बिहार में मिड-डे मील को लेकर पायलट प्रोजेक्ट पहले चरण में ही

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहार में मिड डे मील को लेकर आठ महीने से चल रहा पायलट प्रोजेक्ट पहले चरण में ही बंद हो गया है। इस योजना के तहत मिड डे मील के संचालन से शिक्षकों को मुक्त किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर इसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को सौंप दी गई है। स्कूल संचालन में परेशानी, पढ़ाई प्रभावित होने, अंडा-फल-सब्जी को लेकर विवाद और छात्रों के नामांकन में गिरावट को इसकी प्रमुख वजह बताया गया है। सभी जिलों में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट को 1 फरवरी 2026 से बंद कर दिया जाएगा। राज्य के 71 हजार स्कूलों में पढ़ने वाले 1.09 करोड़ छात्रों को मिड डे मील दिया जाता है। इनमें करीब 40% छात्राएं हैं।

क्या था पायलट प्रोजेक्ट

मई 2025 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को मिड डे मिल के कार्य से मुक्त करने की योजना बनाई थी। दोपहर के भोजन की जिम्मेदारी किसी एक शिक्षक को दी गई थी। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के 534 प्रखंडों के 534 स्कूलों में लागू की गई थी। उद्देश्य था कि प्रधानाध्यापक प्रशासनिक और निगरानी कार्यों से मुक्त होकर शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार पर ध्यान दे सकें।

वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

रिपोर्ट में पायलट प्रोजेक्ट फेल

शिक्षा विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट को पूरे राज्य में लागू करने से पहले 534 स्कूलों का सर्वे कराया। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन स्कूलों में योजना लागू थी, वहां 70% प्रधानाध्यापक फिर भी भोजन संचालन से जुड़े रहे। मिड डे मील की जिम्मेदारी ट्रांसफर होने के बाद भी प्रधानाध्यापकों का कार्यभार कम नहीं हुआ।

फिर से पुरानी व्यवस्था लागू

1 फरवरी 2026 से सभी स्कूलों में मिड डे मील की पुरानी व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत प्रधानाध्यापक और प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति (वीईसी) ही भोजन उपलब्ध कराएंगे। मिड डे मील की निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। अनियमितता मिलने पर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। शिक्षक और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

विवाद से जुड़े मामले

मोतिहारी के पैठानपट्टी मिडिल स्कूल में मई 2025 में प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक के बीच मारपीट। बेतिया के मैनाटांड में मिड डे मील को लेकर विवाद। सारण के एक स्कूल में खराब खाना मिलने की शिकायत। बिहटा के एक स्कूल में मानक के अनुरूप भोजन नहीं मिलने पर जांच में अनियमितता उजागर।

मिड डे मील को लेकर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। इससे छात्रों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। प्रधानाध्यापक की निगरानी में भोजन का वितरण होगा। -**सुनील कुमार**, मंत्री, शिक्षा विभाग

तैयारी | जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र की संभावना तलाशेगी राज्य सरकार, उद्योग विभाग का कार्ययोजना पर काम शुरू, जमीन की हो रही तलाश

राज्य के 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के 31 जिलों में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा। राज्य सरकार इन जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र की संभावना तलाशेगी। इसके लिए उद्योग विभाग ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। उपलब्धता के आधार पर उनका अधिग्रहण किया जाएगा।

पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार और नए क्षेत्रों की स्थापन को लेकर निर्देश दिये थे। उसके बाद से उद्योग विभाग ने अपने स्तर से पहल शुरू कर दी है। इस समय 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र हैं और कई जिलों में ओद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की योजना पर काम हो रहा है। दरअसल, सरकार ने सूबे में नए निवेश की योजना बनायी है। इसके लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के साथ विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की गयी है। निवेश आकर्षित करने के तहत ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, आधुनिक फुड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ पां नए मेगा फूड पार्क स्थापित करना, 100 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पार्कों को विकसित करना, उद्योग-प्रासंगिक कौशल एवं उद्यमिता में सात लाख लोगों को प्रशिक्षित करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय की स्थापना एवं सभी जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र स्थापित करना शामिल है। इन सबके लिए जमीन की आवश्यकता होगी। इसीलिए विभाग ने सभी जिलों में जमीन उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना पर काम प्रारंभ किया है।

- विभाग ने सभी जिलों में जमीन उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना पर काम प्रारंभ किया

पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ के निवेश की योजना

राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की कार्ययोजना पर काम कर रही है। बिहार को भारत के शीर्ष पांच निवेश अनुकूल राज्यों में सम्मिलित करने के लिए उद्योग विभाग देश-दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलनों का आयोजन करेगा, ताकि बड़े से बड़े उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।

अबतक 19 हजार एकड़ जमीन की पहचान

राज्य सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 19 हजार एकड़ जमीन की पहचान की है। इस जमीन का उपयोग सभी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में किया जाएगा, वहीं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा।

"हम राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनायी गयी है। सभी संबंधित जिलों में जमीन की तलाश की जा रही है। हम नए निवेशकों को उनकी सुविधा के अनुसार और उनकी जरूरतों के अनुरूप जिलों में जमीन उपलब्ध कराएंगे। -डॉ. दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री

दो दिवसीय राष्ट्रीय कर सम्मेलन का हुआ उद्घाटन, देशभर के कर विशेषज्ञ जुटे

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार की जरूरत : न्यायमूर्ति सुधीर सिंह

संवाददाता, पटना

वर्तमान समय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है. कर सलाहकारों और कर विशेषज्ञों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे समाधान प्रस्तुत करें, जिससे करदाताओं के विवादित मामलों में कमी आये और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो. ये बातें पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर सिंह ने कहीं. वे शनिवार को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शताब्दी वर्ष व ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स (इस्ट जोन) की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. न्यायाधीश ने चारों संस्थाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि निःस्वार्थ भाव से कर प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में किया जा रहा यह प्रयास प्रशंसनीय है. उन्होंने कहा कि कर कानूनों का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि न्यायसंगत और सरल व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना भी होना चाहिए. मौके पर सम्मेलन के चेयरमैन व बिहार चैंबर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पटना जैसे ऐतिहासिक शहर में इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन होना राज्य के लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी और यह संस्था अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है. चैंबर न केवल उद्योग और व्यापार के हितों की रक्षा करता रहा है, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी उसकी सक्रिय भूमिका रही है.

कर प्रणाली को सहज, पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर बल : ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस वेंकटारमणी ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए चैंबर को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में व्यावहारिक सुधारों पर गंभीर मंथन का यही सही मंच है.

राष्ट्रीय कर सम्मेलन का उद्घाटन करते पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर सिंह, चेयरमैन व बिहार चैंबर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल व अन्य.

पटना सहित छह शहरों की हवा खराब श्रेणी में

चिंता

पटना, मुख्य संवाददाता। प्रदूषण मानकों के लगातार उल्लंघन से राज्य के छह शहरों की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शनिवार को सीवान, पटना, हाजीपुर, सहरसा, बिहारशरीफ और समस्तीपुर की हवा खराब रही। सर्वाधिक प्रदूषित सीवान रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 265 था। वहीं राजधानी पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 236 पर पहुंच गया।

शनिवार को पटना शहर का 80 प्रतिशत इलाका प्रदूषित रहा। सबसे खराब हाल गांधी मैदान इलाके का रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 270 था। दानापुर, समनपुरा और तारामंडल का इलाके की हवा खराब रही। सप्ताहांत के कारण वाहनों का लोड सड़कों पर कम होने के बाद भी अधिकतर इलाके प्रदूषण की चपेट में रहे।

वायु गुणवत्ता सूचकांक के ये हैं मानक

0-50 अच्छा | 51-100 संतोषजनक | 101-200 औसत | 201-300 खराब | 301-400 बहुत खराब | 401-500 खतरनाक | 501 से ज्यादा आपात

बिहारशरीफ	227	बक्सर	169	आरा	106
हाजीपुर	261	राजगीर	175	औरंगाबाद	118
पटना	236	पूर्णिया	135	बेतिया	140
सहरसा	234	गया	149	भागलपुर	124
समस्तीपुर	217	कटिहार	135	मुजफ्फरपुर	148
सीवान	265	अररिया	126	किशनगंज	59

- सीवान राज्य का सबसे प्रदूषित शहर, बिहारशरीफ, हाजीपुर, सहरसा, समस्तीपुर की भी हवा खराब

पटना के विभिन्न इलाकों का हाल

दानापुर	238
तारामंडल	267
गांधी मैदान	270
समनपुरा	218
राजवंशी नगर	169

पानी का छिड़काव और सख्ती बढ़ाने की जरूरत

मौसम में बदलाव यानी धूप निखरने के बावजूद प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी होने की वजह लापरवाही मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माण स्थलों के पास मानकों का घोर उल्लंघन हो रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाने की जरूरत है। प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वाले एजेंसियों पर कार्रवाई की बेहद आवश्यकता है। शनिवार को प्रदूषण के पसरने को विशेषज्ञ नागरिकों के सेहत के लिए खतरनाक बता रहे हैं।

UNITED METALIK

NATIONAL

Hindustan Page
Jansatta Page.

रिकार्ड | 31 दिसंबर तक निगम को मिला 2705 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कर

एमसीडी का अब तक का सबसे बड़ा कर संग्रह

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान संपत्ति कर संग्रह में बड़ा रिकार्ड बनाया है। एमसीडी के कर एवं समाहर्ता विभाग ने इस बार 31 दिसंबर तक 2,705 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कर संग्रह कर लिया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 45 फीसद ज्यादा है। साथ ही 'सुनियो कर माफी' योजना को अब 5 प्रतिशत के मामूली जुर्माने के साथ 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है।

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कुल संपत्ति करदाताओं की संख्या 10,31,177 से बढ़कर 12,43,375 हो गई है, जो लगभग 21 फीसद की वृद्धि को दर्शाती है। निगम ने संपत्ति संग्रह में वृद्धि का श्रेय महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह और निगम आयुक्त अश्वनी कुमार को दिया है। इस संग्रह का मुख्य कारण 'सुनियो कर माफी' योजना 2025-26 रही है। इस योजना के अंतर्गत करदाता वित्तीय वर्ष

वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कुल संपत्ति करदाताओं की संख्या 10,31,177 से बढ़कर 12,43,375 हो गई है, जो 21 फीसद ज्यादा। *इस* कर संग्रह का मुख्य कारण 'सुनियो कर माफी' योजना 2025-26 रही है। इस योजना के अंतर्गत करदाता वित्तीय वर्ष 2025-26 का वर्तमान संपत्ति कर तथा पूर्व के पांच वर्षों के बकाया कर का भुगतान करने पर ब्याज एवं जुर्माने में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

2025-26 का वर्तमान संपत्ति कर तथा पूर्व के पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के बकाया कर का भुगतान करने पर ब्याज एवं जुर्माने में पूर्ण छूट प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी 6 लाख से अधिक ऐसे पंजीकृत करदाता हैं जिन्होंने या तो कम संपत्ति कर दिया है या बिल्कुल भुगतान नहीं किया है।

इस योजना के कारण उन करदाताओं को विशेष लाभ मिला जिन्होंने पूर्व में गलत संपत्ति कर रिटर्न (पीटीआर) दाखिल किया था या कम कर का भुगतान किया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे करदाता जिन्होंने केवल एक या दो वित्तीय वर्षों में ही कर का भुगतान किया था और बाद के वर्षों में कर जमा नहीं किया था, उन्होंने भी इस योजना का लाभ उठाया।

31 दिसंबर 2025 तक लगभग 1.70 लाख करदाताओं ने सुनियो योजना का लाभ उठाया है। इससे निगम को करीब 933 करोड़ रुपए का संपत्ति कर राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें से लगभग 91,000 नए करदाताओं से 320 करोड़ रुपए का कर संग्रह भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुई डाल्फिन की गिनती

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जनवरी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने डाल्फिन संरक्षण को गति देने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से 'प्रोजेक्ट डाल्फिन' के तहत नदी-मुहाना क्षेत्रों में डाल्फिन गिनती शुरू की। 26 शोधकर्ताओं ने तीन नावों से पारिस्थितिक मापदंड दर्ज किए और हाइड्रोफोन जैसी तकनीकों से जलमग्न ध्वनिक निगरानी की।

पहले चरण में बिजनौर से गंगा सागर तक गंगा मुख्यधारा व सिंधु क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र, गंगा सहायक नदियां, सुंदरबन व ओड़ीशा जोड़े जाएंगे। सर्वे में गंगा, सिंधु व इरावदी डाल्फिन के अलावा उनके आवास, खतरे व संरक्षण-प्राथमिकता वाले जीवों का आकलन होगा। यह साक्ष्य-आधारित नीतियों के लिए वैज्ञानिक आंकड़े जुटाएगा। पिछले राष्ट्रव्यापी सर्वे (2021-23) में भारत में 6,327 नदी डाल्फिन मिली थीं।

प्रभु राम के आदर्श पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा : उपराष्ट्रपति

भारत मंडपम में मोरारी बापू द्वारा रामकथा के शुभारंभ के दौरान उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व आचार्य लोकोश मुनि • ध्रुव कुमार

- भारत मंडपम में नौ दिवसीय राम कथा का हुआ शुभारंभ
- उपराष्ट्रपति ने मोरारी वापू के वैश्विक योगदान को सराहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को भारत मंडपम में नौ दिवसीय राम कथा का शुभारंभ किया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य मोरारी बापू द्वारा प्रस्तुत की जा रही 971वीं राम कथा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राम कथा केवल एक महाकाव्य का गायन नहीं, जीवन जीने का एक जीवंत दर्शन है। प्रभु राम के आदर्श पूरी मानवता के लिए प्रेरणा हैं। यह कथा नैतिकता, करुणा और बंधुत्व के उन कालातीत मूल्यों को प्रसारित करती है, जो वास्तव में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का मुख्य आधार रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जीवन में चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, धर्म को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और अंत में सत्य की ही विजय होती है। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द और आचार्य लोकेश सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

समारोह में अयोध्या में राम मंदिर में हुए ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह को याद करते हुए उपराष्ट्रपति भावुक हो गए और उन्होंने इसे भक्तों के धैर्य और सदियों तक चले संघर्ष की जीत का प्रतीक बताया। वहीं, मोरारी बापू के वैश्विक योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बापू वर्षों से विश्वभर में मानवीय चेतना को जगाने और शांति का संदेश फैलाने का कार्य कर रहे हैं। रामायण की सार्वभौमिकता पर उन्होंने कहा कि चाहे संस्कृत की वाल्मीकि रामायण हो, अवधि की रामचरितमानस या तमिल की कंबन रामायण सभी का मूल तत्व केवल धर्म ही है।

जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित सबसे पुराना विधेयक सूची में | संसद | मल्लिकार्जुन खरगे के श्रम मंत्री रहते हुए पेश विधेयक भी शामिल

राज्यसभा में 19 विधेयक लंबित, सबसे पुराना 1992 का

नई दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा)।

राज्यसभा में कुल 19 सरकारी विधेयक लंबित हैं, जिनमें सबसे पुराना जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है और यह 1992 का है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा में लंबित विधेयक सदन के भंग होने पर समाप्त हो जाते हैं, राज्यसभा में लंबित विधेयक कभी समाप्त नहीं होते।

संसद के उच्च सदन के बुलेटिन के अनुसार, वर्तमान में 19 विधेयक लंबित हैं, जिनमें सबसे पुराना 'संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992' है। इस विधेयक में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके तहत राज्य को जनसंख्या नियंत्रण और छोटे परिवार मानदंड को बढ़ावा देना होगा और छोटे परिवार मानदंड को बढ़ावा देना एवं अपनाना मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाएगा।

इस विधेयक में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके तहत राज्य को जनसंख्या नियंत्रण और छोटे परिवार मानदंड को बढ़ावा देना होगा और छोटे परिवार मानदंड को बढ़ावा देना एवं अपनाना मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाएगा। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि यदि किसी सांसद या विधायक के दो से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लंबित विधेयकों में दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 भी शामिल है, जिसका उद्देश्य दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 में संशोधन करना था। इसका लक्ष्य किराया नियंत्रण कानूनों का आधुनिकीकरण करना था, लेकिन इसे किरायेदार और मकान मालिक समूहों से बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। सरकार जहां एक ओर बीज विधेयक 2025 लाने पर काम कर रही है, वहीं लंबित विधेयकों में बीज विधेयक, 2004 भी शामिल है, जिसका उद्देश्य बिक्री, आयात और निर्यात के लिए बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना और गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति को सुविधाजनक बनाना था।

अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 भी लंबित है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के श्रम मंत्री रहते हुए पेश किया गया था। यूपीए दो के दौरान पेश किए गए अन्य लंबित विधेयकों में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक संबंधी कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 रोजगार एक्सचेंज (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013 और संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पुनर्व्यवस्थापन (तीसरा) विधेयक, 2013 शामिल हैं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासन के दौरान पेश लंबित विधेयकों में संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019 शामिल है, जिसका उद्देश्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों को बढ़ाकर पूर्वोत्तर में आदिवासी स्वायत्तता को मजबूत करना, निर्वाचित ग्राम और नगर परिषदों की शुरुआत करना और अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 शामिल है। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 से लंबित है।

Dainik Jagaran Page
Jansatta Page

INTERNATIONAL

विश्व मंच पर दिखेगी ब्रांड झारखंड की झलक

झारखंड को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने और राज्य की खनन व पर्यटन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. सरकार 19 जनवरी, 2026 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की वार्षिक बैठक में हिस्सा ले रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा लेगा. प्रतिनिधिमंडल दावोस के अलावा लंदन का भी दौरा करेगा. प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचिव, उद्योग सचिव, उद्योग निदेशक, जियाडा निदेशक समेत अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे.

पहली बार वैश्विक मंच पर झारखंड की उपस्थिति होगी. ब्रांड झारखंड को इस बार पूरी दुनिया देख सकेगी. झारखंड पहली बार दावोस में आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में भाग ले रहा है. यहां दुनिया भर के तमाम निवेशक शामिल होते हैं. साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे. यह यात्रा राज्य की आर्थिक मजबूती, विविध अवसरों और निवेश की असीमित संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर होगा.इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य झारखंड को एक प्रमुख निवेश स्थल के रूप में प्रमोट करना और विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के नेताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग के रास्ते खोलना है.दूसरी ओर लंदन को निवेश, शिक्षा और पर्यटन का वैश्विक केंद्र माना जाता है, इसलिए दावोस के साथ लंदन को भी इस दौरे में शामिल किया गया है.इस यात्रा के दौरान वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों के साथ भी निवेश पर चर्चा की संभावना है. इस पहल से झारखंड की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और राज्य में रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे.

झारखंड के खनिज : निवेश का व्यापक क्षेत्र

झारखंड में भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% पाया जाता है. कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम और तांबा- चारों रणनीतिक खनिजों की यहां मौजूदगी है. हम देश के शीर्ष कोयला उत्पादक राज्यों में शामिल है. झरिया देश का सबसे बड़ा कोकिंग कोल क्षेत्र है. बोकारो, नॉर्थ कर्णपुरा, राजमहल इस्पात और ऊर्जा उद्योग की रीढ़ है. नीआमुंडी, गुवा, चिरिया (पश्चिम सिंहभूम) भंडार भारत के श्रेष्ठ लौह अयस्क भंडारों में गिना जाता है. भारत का पहला तांबा खनन क्षेत्र झारखंड में है. इनमें सिंहभूम तांबा पट्टी- घाटशिला, मुसाबनी, राखा प्रमुख हैं. बॉक्साइट, अभ्रक (माइका), यूरेनियम, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और अन्य खनिज भी हमारे पास भरपूर है. ये वे संपदा हैं, जो निवेश के आमंत्रण का आधार, संभावना और भविष्य हैं.

झारखंड में इस पहल से 50 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की संभावना

झारखंड में 50 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की संभावना है. झारखंड में देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा मौजूद है. निवेशकों को खनन क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा स्टील क्षेत्र में निवेश के बाबत कहा गया है कि यहां पहले से ही टाटा स्टील व सेल के प्रतिष्ठित प्लांट हैं. साथ ही विश्वस्तरीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है. पर्यटन के लिए कहा गया है कि यहां खूबसूरत झरने, वाइल्ड लाइफ सैंचुअरी, आदिवासी विरासत और इको टूरिज्म डेस्टिनेशन निवेशकों का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, आधारभूत संरचना के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेस-वे और सस्ते घर की स्कीम के लिए भी निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है.

टेक हब डेवलपमेंट : सरकार ने टेक हब डेवलपमेंट के लिए भी निवेशकों को आमंत्रित किया है. खासकर रांची और जमशेदपुर में प्रस्तावित आइटी पार्क के लिए. वहीं, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन में निवेश के लिए बताया गया है कि रिच बायोडायवर्सिटी, ऑर्गेनिक खेती की संभावना और ग्लोबल अपील वाले पारंपरिक फूड प्रोडक्ट्स में भी निवेश की संभावना है. सरकारी प्रोत्साहनों के साथ 79,714 वर्ग किलोमीटर में सोलर और बायोमास एनर्जी में निवेश की बात कही गयी है. टेक्सटाइल क्षेत्र में भी निवेश के लिए कहा गया है कि कुशल कारीगरी, तसर सिल्क विरासत और बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के साथ उभरता हुआ टेक्सटाइल हब निवेशकों के लिए तैयार है.

इंडिया पैवेलियन में झारखंड

दावोस में झारखंड की भागीदारी का केंद्रीय विषय 'प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास' है. यह विषय वर्ष 2026 के विश्व आर्थिक मंच के फोकस- सतत विकास, लचीलापन, विश्वास और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन से पूरी तरह मेल खाता है. झारखंड सरकार का विकास दृष्टिकोण आर्थिक प्रगति, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समावेशन के संतुलन पर आधारित है, जिसमें राज्य की प्राकृतिक संपदा और आदिवासी विरासत की महत्वपूर्ण भूमिका है.

इन विषयों पर होगी चर्चा

झारखंड प्रतिनिधिमंडल इंडिया पैवेलियन सहित विभिन्न मंचों पर राज्य-नेतृत्व वाले सत्रों, संवादों और आधिकारिक बैठकों में भाग लेगा. इन बैठकों में निवेश प्रोत्साहन, जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन, सतत औद्योगिक विकास, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा संरक्षण और दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास जैसे विषयों पर चर्चा होगी.

वेबसाइट लांच

इस यात्रा से संबंधित जानकारी www.jharkhandatdavos.co.in पर उपलब्ध होगी. राज्य की आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स- एक्स(ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जानकारी साझा की जायेगी.

खनन, ग्रीन एनर्जी में निवेश के लिए आमंत्रित

दावोस वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम में झारखंड सरकार निवेशकों को खनन, ग्रीन एनर्जी, आइटी पार्क से लेकर इको टूरिज्म में निवेश के लिए आमंत्रित करेगी. निवेशकों को पूर्व में ही जानकारी देने के लिए सरकार ने झारखंड एट दावोस वेबसाइट बनायी है.

दावोस : स्विट्जरलैंड का छोटा पहाड़ी शहर

दावोस स्विट्जरलैंड का एक छोटा पहाड़ी शहर है, जो यूरोप के आल्प्स पर्वत क्षेत्र में स्थित है. यह सर्दियों के पर्यटन और स्की रिजॉर्ट के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दुनिया में इसकी पहचान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से बनी है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य है सरकार, उद्योग और समाज को साथ लाकर दुनिया को बेहतर बनाना. दावोस को आज वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और नीति-निर्माण का केंद्र माना जाता है. हर साल यहां एक ऐसा मंच लगता है, जहां दुनिया के बड़े नेता, कॉरपोरेट प्रमुख, नीति निर्माता और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एक साथ बैठकर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं. इसी वजह से दावोस को अक्सर 'ग्लोबल पावर मीटिंग प्लेस' भी कहा जाता है.

ऐसे बना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत 1971 में हुई. इसकी शुरुआत संस्थापक प्रो क्लॉस श्वाब ने की. शुरुआत में इसका नाम यूरोपीय मैनेजमेंट फोरम था. बाद में इसका दायरा यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बन गया.

क्यों बनाना पड़ा डब्ल्यूइएफ

दरअसल, 1970 के दशक की शुरुआत में यूरोप की कंपनियों को बेहतर बनाने की जरूरत थी. तब यूरोपीय कंपनियां अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता में पीछे थीं. इसी कमी को दूर करने के लिए एक ऐसा मंच बनाने की जरूरत महसूस की गयी थी, जहां बिजनेस लीडर, नीति विशेषज्ञ और सरकारें एक-दूसरे से सीख सकें. इसकी बैठकों का आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी महीने में होता है.

कौन करता है फंडिंग

इस फोरम को करीब 1000 मेंबर कंपनियों द्वारा फंड दिया जाता है, जिनमें खासकर ग्लोबल कंपनियां होती हैं, जिनका टर्नओवर पांच अरब डॉलर से भी अधिक होता है. साथ ही तमाम सरकारों से मिली सब्सिडी से भी इस संस्था की फंडिंग होती है.

इन विषयों पर होती है चर्चा

फोरम में वैश्विक अर्थव्यवस्था, निवेश और व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो-पॉलिटिक्स, रोजगार और विकास- इन विषयों पर चर्चा होती है यानी आने वाले वर्षों की दुनिया की दिशा यहीं काफी हद तक तय होती है.

भारतीय राज्य कैसे लेते हैं भाग

दरअसल, इस फोरम में राज्य अलग देश की तरह नहीं, बल्कि भारत के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर भाग लेते हैं. राज्यों को निवेश प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार और डब्ल्यूइएफ के समन्वय से अलग-अलग सेशंस निवेशकों से द्विपक्षीय बैठक करने का अवसर मिलता है. अवसर इसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उद्योग सचिव और उनकी निवेश प्रमोशन एजेंसियां भाग लेने के लिए जाती हैं. इसमें राज्य अपने लिए स्टेट इनवेस्टमेंट पिच तैयार करता है.

ऐसे संपन्न होते हैं डब्ल्यूइएफ के सत्र

- पैनल चर्चा
- वन-टू-वन मीटिंग
- निवेश प्रस्ताव
- नीति संवाद
- एमओयू
- ग्लोबल टेबल पर बहस

ज्यूरिख में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के संबंध में जानकारी देते हुए स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत मृदुल कुमार

यात्रा का मकसद राज्य का आर्थिक विकास

दावोस दौरे का मकसद आर्थिक और विकासात्मक है. इससे निवेश, उद्योग, रोजगार और झारखंड की वैश्विक पहचान को बढ़ावा मिलेगा.

निवेश आकर्षित करना

वैश्विक कंपनियों, उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात कर उन्हें झारखंड में उद्योग लगाने,मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, स्टील, ऊर्जा, आइटी, फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित करना.

झारखंड की ब्रांडिंग

दावोस जैसे मंच पर राज्य को एक निवेश-अनुकूल, संसाधन-समृद्ध, श्रम व कौशल उपलब्ध राज्य के रूप में प्रस्तुत करना.

एमओयू और निवेश प्रस्ताव

इस दौरान, निवेश समझौते, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट साइन करना, ताकि भविष्य में नयी परियोजनाएं राज्य में आएं.

रोजगार सृजन का लक्ष्य

निवेश से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, सहायक उद्योगों का विस्तार करना.

वैश्विक नीति और तकनीक की समझ

ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर चर्चा तथा इन वैश्विक रुझानों को अपनी नीतियों से जोड़ना.

केंद्र व अन्य राज्यों से समन्वय

केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समन्वय और प्रतिस्पर्धी निवेश रणनीति बनाना.

प्रभात खबर इंपैक्ट फीचर

PR 370980(IPRD)25-26

तीन वर्षों में ईयू को दोगुना हो जाएगा निर्यात

नई दिल्ली, प्रेट्र: निर्यातकों का कहना है कि भारत और 27 देशों के संगठन यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने से वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, रत्न व आभूषण के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। समझौते के लिए वार्ता के समापन की घोषणा 27 जनवरी को की जा सकती है। उद्योग का अनुमान है कि एफटीए के कारण टैरिफ समाप्त होने से अगले तीन वर्षों में ईयू को निर्यात दोगुना हो जाएगा।

निर्यातकों ने बताया कि यह एफटीए निर्यात के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित ढांचा प्रदान करेगा, जिससे भारतीय कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश योजना बनाने, यूरोपीय मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होने और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए शक्तिवेल का कहना है कि यह एफटीए किसी एक बाजार पर हमारी निर्भरता को कम करने में

- भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता के समापन की घोषणा 27 जनवरी को संभव
- वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन समेत कई क्षेत्रों में निर्यात बढ़ेगा

एक गेम चेंजर होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए उच्च टैरिफ के कारण घरेलू निर्यातकों को उच्च लागत और एक प्रमुख बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसने भारतीय निर्यातकों को निर्यात बाजार में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है।

एफटीए वार्ता में उन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, जहां भारत का यूरोपीय संघ को निर्यात मजबूत है। 11 और परिधान, फार्मास्यूटि इंजीनियरिंग सामान, पेट्रो उत्पाद और रसायन केंद्र म वर्तमान में वस्त्र और परिधान पर ईयू में 12-16 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है, जिससे भारतीय वस्तुएं कम प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। यूरोपीय संघ में तैयार कपड़ों के लिए औसत आयात शुल्क 12 प्रतिशत है, जो भारत को यूरोपीय संघ की सामान्यीकृत प्राथमिकता योजना (जिसे अब जीसीटीएस कहा जाता है) के तहत विशेष पहुंच मिलने के कारण 9.6 प्रतिशत हो जाता है।

कानपुर स्थित ग्रोमोर इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक यतेंद्र सिंह सचान ने कहा कि घरेलू चमड़ा निर्यातकों को इस अवसर का उपयोग करके निर्यात को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना चाहिए। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) का कहना है कि एक व्यापक भारत-ईयू एफटीए का समापन न केवल समय पर है, बल्कि यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

EDITORIAL

Jansatta Page
Dainik Jagaran Page

विश्व को अस्थिर करता अमेरिका

संजय गुप्त

डोनाल्ड ट्रंप केवल ग्रीनलैंड में ही कब्जा करने के लिए उतावले नहीं दिख रहे हैं। वे ईरान में भी सैन्य हस्तक्षेप करने के संकेत दे रहे हैं

अंतरराष्ट्रीय नियम-कानून को धता बताकर वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और वहां के राष्ट्रपति के अपहरण की चर्चा अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का एलान कर दिया। हालांकि ग्रीनलैंड को हासिल करने की बातें उन्होंने पहले भी की थीं, लेकिन तब अंतरराष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से यूरोप ने उनकी बातों को हल्के में लिया था, लेकिन अब उनकी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ट्रंप डेनमार्क के इस स्वायत्तशासी क्षेत्र पर हर हाल में कब्जे के इरादे जता रहे हैं। इस कारण सैन्य संगठन नाटो में शामिल कुछ यूरोपीय देश अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड भेज रहे हैं। ग्रीनलैंड के साथ डेनमार्क के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ट्रंप के इरादों को पूरा नहीं होने देंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति किसी की नहीं सुन रहे हैं। वे नाटो का अंत होने की डेनमार्क की चेतावनी का उपहास उड़ाकर कह रहे हैं कि यदि आज से पांच सौ साल पहले डेनमार्क की कोई नौका ग्रीनलैंड पहुंची तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह उसका हो गया।

ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यहां तेल, गैस और दुर्लभ खनिज के भंडार हैं। यहां की बर्फ पिघलने के कारण इन संसाधनों के दोहन की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जाहिर है कि इन पर ट्रंप की भी निगाह है। इसके अलावा इस द्वीप का सामरिक महत्व भी है। चूंकि ग्रीनलैंड के साथ उसके आसपास की भी बर्फ पिघल रही है, इसलिए समुद्री रास्तों से वहां तक रूस और चीन की पहुंच आसान हो रही है। इसी कारण ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर रूस और चीन की निगाह है।

हालांकि अतीत में भी अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाने की बातें की थीं, पर वे कभी इस दिशा में आगे नहीं बढ़े। हां, एक समझौते के तहत 1951 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपना सैन्य अड्डा कायम कर लिया। यह अभी भी है। ट्रंप का तर्क है कि रूस और चीन का ग्रीनलैंड पर वर्चस्व कायम हो, इसके पहले अमेरिका को उसे अपना हिस्सा बना लेना चाहिए। रूस का कहना है कि ट्रंप अकारण यह कह रहे हैं कि वह ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। जो भी हो, आज यह नहीं कहा जा सकता कि रूस या फिर चीन अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से रोक सकेंगे। इसका कारण यह है कि यूरोपीय देश रूस की मदद लेने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वह पहले से ही उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। यूक्रेन के खिलाफ रूस

अवधेश राजपूत

के युद्ध ने यूरोपीय देशों को सशंकित कर रखा है। ऐसे में यदि ट्रंप ग्रीनलैंड पर सच में कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ें तो हैरानी नहीं। डेनमार्क और यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद एक चिंताजनक तथ्य यह है कि अमेरिका में कई सांसद ट्रंप के इस विचार से सहमत हैं कि ग्रीनलैंड को वैसे ही अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहिए, जैसे अलास्का को बनाया गया था। कहना कठिन है कि आगे क्या स्थितियां बनेंगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के रवैये से यूरोप के साथ-साथ शेष विश्व भी चिंतित है।

ट्रंप केवल ग्रीनलैंड में ही कब्जा करने के लिए उतावले नहीं दिख रहे हैं। वे ईरान में भी सैन्य हस्तक्षेप करने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने यह कहा कि फिलहाल ईरान में दखल देने की जरूरत नहीं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं की ईरान की कट्टरपंथी इस्लामी सत्ता उन्हें स्वीकार नहीं। वास्तव में अमेरिका को वह कोई भी देश रास नहीं आता, जो उसके इशारे पर न चले। अमेरिका ने इस आधार पर ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं कि वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इन प्रतिबंधों के कारण ही ईरान आर्थिक संकट से घिरा और उसके चलते वहां लोग सड़कों पर उतर आए। ईरानी सत्ता अपने लोगों की बात सुनने के बजाय उनकी आवाज सख्ती से दबा रही है। इसके चलते वहां सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ट्रंप ईरान की उथल-पुथल का लाभ उठाने की कोशिश में दिखते हैं। वे कह रहे हैं कि ईरान के लोग अपना विरोध जारी रखें। ईरान के प्रति ट्रंप के आक्रामक रवैये पर रूस और चीन तो आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देश दुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। ट्रंप की ईरान के तेल भंडारों पर भी निगाह है और वे यह नहीं चाहते कि वह अपना तेल व्यापार डालर के अलावा अन्य मुद्राओं में करे और इस तरह डालर के प्रभुत्व को चुनौती दे। इसके चलते आशंका यही है कि ट्रंप मौका देखकर ईरान में लोकतंत्र बहाली की आड़ में वहां तख्तापलट की कोशिश कर सकते हैं। इसमें ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी मददगार हो सकते हैं, जो निर्वासित होकर अमेरिका में रह रहे हैं। उनका कहना है कि वे ईरान लौटेंगे। यदि ट्रंप ने ईरान में हस्तक्षेप किया तो यह देश वैसी ही अस्थिरता से घिर सकता है, जैसे इराक घिर गया था। ध्यान रहे इराक को भी अमेरिका ने मूलतः उसके तेल भंडारों के कारण ही निशाना बनाया था।

ट्रंप ईरान के साथ उसके सहयोगियों का भी संकट बढ़ा ही रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी देश उससे व्यापार करेंगे, उस पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। ईरान से व्यापार करने वाले प्रमुख देशों में चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत हैं। साफ है कि ट्रंप के रवैये से भारत की समस्या भी बढ़ने वाली है। चूंकि ईरान में सामाजिक असंतोष के कारण अस्थिरता व्याप्त है, इसलिए ट्रंप प्रत्यक्ष न सही, परोक्ष हस्तक्षेप कर सकते हैं-ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसके पीछे पश्चिमी ताकतों का हाथ था। ईरान के मामले में तो यह खुलकर सामने आ रहा है कि अमेरिका वहां अशांति बढ़ा रहा है। पता नहीं ट्रंप के मन में क्या है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरका ने जिस भी देश में छल-बल से सत्ता परिवर्तन कराया, वे अस्थिरता से ग्रस्त हुए। ट्रंप की मनमानी इसलिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि विश्व के प्रमुख देश अमेरिका को सीधी चुनौती दे सकने में सक्षम नहीं और संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल असहाय है। ऐसे में आने वाले समय में ट्रंप के चलते विश्व में अस्थिरता फैले तो आश्चर्य नहीं।

response@jagran.com

मित्रता की बदलती परिभाषा

हास्य-व्यंग्य मित्रता ऐसा रिश्ता है, जो सबसे ज्यादा अबूझ रहा है। यह देशकाल, परिस्थिति और सुविधा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। मित्रता की जहां हजारों मिसालें मिलती हैं, वहीं इसके आघात से पीड़ित होने वाले भी कम नहीं। अगर मित्रता न होती तो शायद विश्वासघात या धोखा जैसे शब्द अस्तित्व में ही नहीं आते। आजकल इस शब्द ने और विस्तार कर लिया है। यदि कोई आपको बार-बार अपना मित्र बताए तो उससे सावधान हो जाएं। सीधे-साधे और सच्चे मित्र की बात करें तो ये हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। इनकी मित्रता जितनी सहज होती है, धोखा भी उसी सहजता से होता है। यही मित्र हैं जो आपको 'आत्मनिर्भर' बनाते हैं। सामान्य मित्र कुछ अधिक योगदान नहीं कर पाते। ये स्वभावतः भीरु किस्म के होते हैं। ऐसे दोस्त या तो दस-बीस हजार की चपत लगा पाते हैं या आपकी जरूरत में आपसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं।

मित्रों में सबसे कम खतरनाक साहित्यिक मित्र होते हैं। इनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होतीं। अपनी नई किताब आने पर बेचारे आपसे न्यूनतम बलिदान चाहते हैं। इससे बचने का एकाध उपाय तो है, पर ज्यादा कारगर नहीं है। जब कोई पुराना मित्र आपको लगातार दो दिन 'सुप्रभात' के संदेश देने लगे, समझिए उसकी नई किताब का कवर और आपका बटुआ फटने वाला है। तीसरी बार

संतोष त्रिवेदी

डिजिटल दुनिया की मित्रता और शत्रुता मात्र एक 'क्लिक' दूर है। यहां 'अमित्र' होने का बदला 'ब्लाक' करके लिया जाता है

में पक्का किताब की सूचना आएगी। आप लप्प-से बधाई भेजेंगे। बस यही मौका होगा, जब आप 'डिजिटल-अरेस्ट' हो जाएंगे। किताब का लिंक खोले बिना आपकी जान नहीं छूटने वाली। आप यदि समझदार हुए तो दो-ढाई सौ रुपये में छूट जाएंगे। यदि अतिरिक्त समझदारी दिखाई तो आपकी कुंडली खुलने में देर नहीं लगेगी। आपके दूसरे मित्रों में आपके विस्मरणीय योगदानों को पल भर में अविस्मरणीय बना दिया जाएगा।

सबसे अच्छे दोस्त चिरकुट-टाइप के होते हैं। ये चाय-पानी तक में संतोष कर लेते हैं। भूल कर भी कभी इनसे भुगतान मत करवा देना। इतने कम इन्वेस्टमेंट में तो दुश्मन भी नहीं मिलते, दोस्त कहां से मिलेंगे। इनकी एक बड़ी अच्छाई है। ये वफादार होते हैं। जब तक आप उनका ख्याल रखते हैं, वे आपका ढोल बजाते रहेंगे। इनकी मित्रता को शत्रुता में 'कन्वर्ट' करने के बारे में सोचना भी मत। हां, आभासी मीडिया में दोस्ती बड़े हिसाब-किताब से निभाई जाती है। यहां बने मित्रों को सामान्य मित्र समझना बड़ी भूल है। बड़े से बड़ा लेखक, अफसर या पत्रकार आपका मित्र होते हुए भी वैसा नहीं होता, जैसा वास्तविक मित्र होता है। उनके लिखे पर नियमित टीप न करने पर आप 'अमित्र' हो सकते हैं। इस दुनिया की मित्रता और शत्रुता केवल एक 'क्लिक' दूर रहती है। यहां 'अमित्र' होने का बदला 'ब्लाक' करके लिया जाता है। लोग अच्छे या बुरे लेखन के बजाय 'लाइक' और 'कमेंट' से परखे जाते हैं। कहने भर को यह आभासी मीडिया है, पर यहां दोस्ती से ज्यादा दुश्मनियां निभाई जाती हैं। इसलिए ज्यादा समझदार लोग दूसरों के लिखे पर कुछ नहीं बोलते।

ऐसे मित्र जो आपके ही रचना-क्षेत्र में सक्रिय हैं, वे अक्सर इनबाक्स में ही 'बेहतरीन' लिखना पसंद करते हैं। ज्यादा हुआ तो आपको फोन करके शाबाशी देंगे, पर सार्वजनिक रूप से कभी टिप्पणी नहीं करते। उनको भ्रम होता है कि एक-दो पंक्तियां खुलेआम लिख देने से कहीं उनका 'मित्र' अमर न हो जाए। कई बार खतरा यह भी होता है कि उनकी प्रतिक्रिया से उनके गैंग के दूसरे सदस्य न बिदक जाएं। इसलिए ऐसे मित्र 'स्लीपर सेल' की तरह काम करते हैं और ऐसे ही लोग साहस, सरोकार और सच्चाई पर लगातार लिखते रहते हैं। मित्रता का पूरी ईमानदारी से निर्वाह यही प्राणी करते हैं।

response@jagran.com

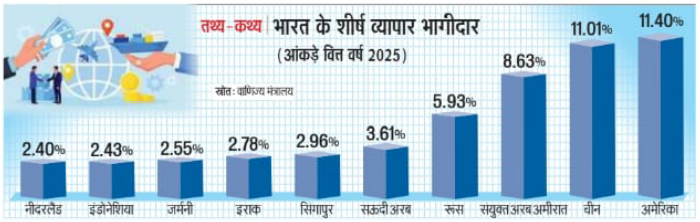

> सोशल मीडिया के वक्त में, जब मुंह से निकला महज एक बहका शब्द देश-दुनिया के किसी भी हिस्से में अंगारे बो सकने की कुव्वत रखता हो, तब क्या हमारे नेताओं को देशहित में सोच-समझकर नहीं बोलना चाहिए? वे भूल क्यों जाते हैं? देश किसी भी चुनाव और सत्ता-सदन से बड़ा होता है।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

राजनीति का विभाजक एजेंडा

शशि शेखर

आजकल

हमारे वैचारिक आभामंडल को चुनाव की मौसमी छूत ने जकड़ लिया है। एटम बमों के जोर पर ऐंठी इस दुनिया में जब तरह-तरह के पलीते लगाए जा रहे हों, तब हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? वे इस खतरनाक वक्त में देश को एकजुट करने के बजाय विभाजक कुतर्क बुन रहे हैं। उनकी ऐसी हरकतों से यह मुल्क खुद को शर्मसार महसूस करता है।

भरोसा न हो, तो बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव पर नजर डाल देखिए। ये वार्ड स्तर के चुनाव थे, लेकिन इसे जीतने के लिए क्या-क्या नहीं किया गया? कल तक जो ठाकरे बंधु एक-दूसरे के खिलाफ थे, वे एकजुट हो गए। राज ठाकरे के भाषणों में शिवसेना का लगभग छह दशक पुराना तमिल विरोध उभर आया। वह तमिलभाषी मुंबइकरों को 'रसमलाई' कह रहे थे। उनके लिए 'लुंगी' और 'पुंगी' जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये शब्द शिवसेना के जनक बालासाहेब ठाकरे के पुराने शब्दकोश से उधार लिए गए थे। बालासाहेब ने 1960-70 के दशक में दक्षिण भारतीयों की खिलाफत अपनी कार्टून साप्ताहिक मैगजीन *मार्मिक* और जनसभाओं के जरिये शुरू की थी। सवाल उठता है, मुंबई के विकास में अगर गैर-मराठी लोगों की सतत भूमिका है, तो फिर वे वहां के हवा-पानी पर हक-हुकूक क्यों नहीं रख सकते? इनमें से तमाम की कई पीढ़ियां यहां खप चुकी हैं। यह 'आमची मुंबई' अब उनका स्थायी पता है।

फिर ऐसा क्यों हो रहा है?

बीएमसी से कहीं 30 साल पुराना प्रभुत्व खत्म न हो जाए, इसलिए ठाकरे परिवार ने बालासाहेब के 'मराठा मानुष' नारे को नए रंग-रोगन के साथ पेश करने की कोशिश की। ठाकरे बंधु राजनीति के प्रचलित भूगोल को अनदेखा कर उस पुराने टोटके पर यकीन कर रहे थे कि भड़की हुई भावनाएं लोगों को एकजुट करती हैं। बिखराव रोकने की बात पर मुझे पवार परिवार याद आ गया। आपको याद होगा कि किस तरह शरद पवार की पार्टी में उनके भतीजे अजीत पवार ने सेंध लगाई थी। बात इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया था। सुप्रिया शरद पवार की पुत्री होने के साथ उनकी सियासी वारिस भी हैं। मतलब साफ है, बीएमसी चुनाव ने वह कर दिखाया, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नहीं कर सके।

यह चमत्कार कैसे हुआ?

जवाब दुरूह नहीं है। बीएमसी का सालाना बजट लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का है। यह देश की सबसे अमीर नगर इकाई है और इसका बजट नौ राज्यों के सालाना आय-व्यय से ज्यादा है। कभी बालासाहेब ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका पर कब्जा कर शिवसेना को यहां तक पहुंचाया था। महाराष्ट्र के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण महानगर की बादशाहत इस प्रदेश की सियासी दशा-दिशा तय करती है। इस पर कब्जे के लिए राजनीतिक परिवार आपस में लड़ सकते हैं, पुनः जुड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा विभाजित हो सकते हैं। और तो और, पार्टियों के व्हिप तक बिखर सकते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के इन चुनावों में मंत्रालय में साथ बैठने वाली शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजीत) और भाजपा इसीलिए कई क्षेत्रों में आमने-सामने थीं। अंबरनाथ नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए तो कमाल ही हो गया। भाजपा और कांग्रेस सभासदों ने हाथ मिला लिए। इससे दिल्ली तक हंगामा मच गया था।

इतनी बेमेल संधियों का नतीजा क्या निकला?

भाजपा आगे निकल गई। ठाकरे और पवार परिवारों को एक बार फिर हाथ मलना पड़ गया। कई चुनाव गवाह हैं, ऐसे बेपेंदी के गठबंधनों का वक्त लद चुका है। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता कारवां भी यही मुनादी करता है कि लक्ष्य, सिद्धांत और कार्य-व्यवहार की एकजुटता सतत सफलता की कुंजी है। इस चुनाव ने पुनः जग-जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस अपने

साथियों के लिए घातक साबित हो रही है।

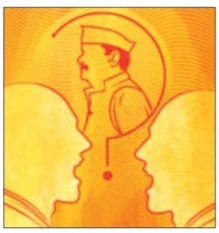

महाराष्ट्र के चुनाव तो जैसे-तैसे निपट गए। अब पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी बिगुल बजने के साथ अलगाववादी नफरत का अलाव सुलग उठा है। कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों के दौरान ममता बनर्जी ने जो किया, वह अभूतपूर्व था। इस छापे के दौरान ही वह चुनाव संचालन करने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर पहुंच गईं। वह और उनके साथी वहां से तमाम फाइलें व कागजात उठा लाए। तृणमूल सहित समस्त विपक्षी नेता कहते आए हैं कि ईडी चुनाव के समय सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ सक्रिय होता है। तृणमूल का आरोप है कि ईडी का यह छापा किसी आर्थिक घोटाले की जांच नहीं, बल्कि हमारे चुनाव संबंधी दस्तावेजों को उठा ले जाने के लिए प्रायोजित किया गया था।

ममता की इस हरकत पर देश की आला अदालत ने उन्हें जमकर फटकारा है। बंगाल सरकार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में जो प्राथमिकी दर्ज की थी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। आपको याद होगा कि इससे पहले झारखंड और तमिलनाडु में भी ऐसी रिपोर्टें दर्ज हुई थीं। बाद में उन्हें अदालत ने रद्द कर दिया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। गई 11 जनवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। स्टालिन की मांग है कि मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात कर प्रस्तावित संविधान सुधारों में तमिल आबादी के अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन हासिल करें। पिछले साल श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या के दिल्ली दौरे के दौरान भी स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कच्चातिवु द्वीप वापस लेने की मांग की थी। कच्चातिवु द्वीप और श्रीलंकाई तमिलों के साथ भेदभाव दशकों पुरानी समस्या है। इसी के चलते पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जान गंवानी पड़ी थी, पर राजनीति नई बोतलों में पुरानी जहरीली शराब बेचने का अनवरत उपक्रम बन गई है।

स्टालिन के भतीजे और द्रमुक सांसद दयानिधि मारन इस आग में अपने तरीके से घी डाल रहे हैं। मंगलवार को चेन्नई के एक सरकारी महिला महाविद्यालय में अलगाववादी भाषण देते हुए उन्होंने कहा, 'यह आत्मविश्वास तमिलनाडु में है, जहां हम लड़कियों से कहते हैं कि पढ़ो और लगातार पढ़ो। उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? लड़कियो, काम पर मत जाओ, घर पर रहो, रसोई में रहो, बच्चे पालो, यही तुम्हारा काम है।'

स्टालिन की तरह खुद को देशभक्त बताने वाले फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी चुनाव जीतने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बांग्लादेश में भारत-विरोध बढ़ रहा है। वहां के हिंदुओं की दिक्कतों में ऐसे बयान बढ़ोतरी करते हैं।

सोशल मीडिया के वक्त में, जब मुंह से निकला महज एक बहका शब्द देश-दुनिया के किसी भी हिस्से में अंगारे बो सकने की कुव्वत रखता हो, तब क्या हमारे नेताओं को देशहित में सोच-समझकर नहीं बोलना चाहिए? वे भूल क्यों जाते हैं? देश किसी भी चुनाव और सत्ता-सदन से बड़ा होता है।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

वो लम्हा

हसरत मोहानी
स्वतंत्रता सेनानी एवं शायर

इंकलाब जिंदाबाद लगा दिया नारा

वह अपने भाषणों में गुलाम मुल्क की ऐसी तस्वीर खींचते हैं कि दिल भर आता है, अश्क बहने लगते हैं, लेकिन आज उनके तेवर-कलेवर काफी बदले हुए हैं। उन्होंने लगे हाथ यह भी प्रस्ताव रख दिया, 'अब हमें अपने मुल्क के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए।'

अहमदाबाद में साल 1921 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत खास था। तब पहली बार खादी के तंबू तने थे। नेताओं के कंधे पर खादी के बैग सजे थे। ऐसा मालूम पड़ता था, मानो गुलाम मुल्क को पहली बार जिस्म ढकने के लिए कपड़े नसीब हुए हों। दिसंबर की गुनगुनी ठंड में खादी के सौंधी महक घुली हुई थी। यह खुशी मुसलसल उमड़ रही थी कि कुछ नया होने वाला है।

एक शायर साहब भी अधिवेशन में शरीक थे। उनकी बारी आई, तो उन्होंने कहा, 'अब छोड़ दीजिए उम्मीद कि अमन-चैन से आपको आजादी मिलेगी, अब तो हथियार उठाने पड़ेंगे। अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी जल्द नहीं मिलेगी। हम कब तक फिरंगियों के जूतों तले जुल्म सहेंगे?' बाकी नेताओं ने उनकी ओर गौर किया, अरे यह तो हसरत मोहानी साहब हैं। अक्सर अपने भाषणों में गुलाम मुल्क की ऐसी तस्वीर खींचते हैं कि दिल भर आता है, अश्क बहने लगते हैं, लेकिन आज उनके तेवर-कलेवर काफी बदले हुए हैं। उन्होंने लगे हाथ यह भी प्रस्ताव रख दिया, 'अब हमें अपने मुल्क के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। हमें आधी नहीं, पूरी आजादी चाहिए।'

यह कांग्रेसियों के लिए नई बात थी। हलचल मच गई। पूर्ण स्वराज की मांग हो रही है। अनेक नेताओं ने यही सोचा कि हसरत साहब बौरा गए हैं, लेकिन कांग्रेस के ही एक अन्य सदस्य स्वामी कुमारानंद ने भी पूर्ण स्वराज के पक्ष में ध्वज फहरा दिया। अब यह कांग्रेस के लिए निर्णायक मोड़ बन गया। कांग्रेस पूरी तरह से कानून-व्यवस्था के तहत वैध तरीकों से काम करती थी। उसकी मांग यही होती थी कि भारतीयों के साथ नाइंसाफी न हो। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारतीयों को ज्यादा हक हासिल हो जाएं, पर यहां तो पहली बार किसी ने पूर्ण स्वराज की मांग रख दी।

जैसा होना था, गांधीजी के नेतृत्व में शायर साहब के प्रस्ताव को एहसासे-कमतरी की कुछ दलीलों के सहारे किनारे कर दिया गया, लेकिन शायर साहब ने अपने भाषण का समापन करते हुए जो नारा लगाया- *इंकलाब जिंदाबाद*, वह सबके जेहन में बैठ गया। इस नारे ने पूर्ण स्वराज की मांग के बीज बो दिए।

हसरत यहीं नहीं थमे, जब वह मुस्लिम लीग के सम्मेलन में गए, तो वहां भी उन्होंने मांग रख दी कि भारत को 1 जनवरी, 1922 से स्वतंत्र घोषित किया जाना चाहिए और इसका नाम संयुक्त राज्य भारत रखा जाना चाहिए। आजादी के लिए जरूरत पड़ जाए, तो गुरिल्ला युद्ध शुरू किया जाना चाहिए। बहरहाल, मुस्लिम लीग ने भी हसरत की मांग को हाशिये पर कर दिया और कुछ ही दिनों बाद हसरत फिर जेल में डाल दिए गए।

वैसे, हसरत मोहानी का जेल से नाता पुराना था। कैद-ए-बा-मशक्कत में हर दिन चक्की पीसते थे। आजादी के लिए बहुत सख्त थे। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी आवाज कभी नरम नहीं हुई, पर वह असलियत में मोहब्बत से सराबोर मुकम्मल इंसान थे। मौका मिलते लिखने बैठ जाते थे। जेल में रहते हुए ही उन्होंने हरदिल अजीज गजल लिखी- चुपके-चुपके *रात दिन आंसू बहाना याद है / हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।*

उनकी कलम में इश्क की स्याही भरी थी और उन्होंने लिखा- *कुव्वत-ए-इश्क भी क्या शय है कि होकर मायूस/ जब कभी गिरने लगा हूं तो संभाला है मुझे।* उन्हें कृष्ण बहुत प्रिय थे। एक बांसुरी पास रखते थे और बजाते थे। जब कैद में उनसे तमाम सामान जब्त किए जाते थे, तब वह गुहार लगाते, 'यह बांसुरी मेरे पास रहने दीजिए, यह तो कृष्णजी की है।' करीब हर जन्माष्टमी वह मथुरा जाते थे। कृष्ण के प्यार में उन्होंने लिखा है- *बरसाना-ओ-नंद-गांव में भी/ देख आए हैं जल्वा हम किसी का।* हसरत के 13 दीवान हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा कैद में रहते तैयार हुए।

वह हिंदू-मुस्लिम एका और अखंड भारत के गजब हिमायती थे। जब मुस्लिम लीग ने यह ठान लिया कि मजहब के नाम पर मुल्क बंटेगा, तब वह लीग से अलग हो गए। आजादी के बाद भारत में ही रहे और आजाद भारत के संविधान लेखन में योगदान दिया। वह मथुरा से मक्का और मास्को तक अमन-चैन-खुशहाली के ख्वाब देखते थे। स्वदेशी के गजब पैरोकार हसरत ने कभी भी सांसद के रूप में किसी सरकारी सहूलियत का फायदा नहीं लिया। अपने पैसे से किराया चुकाकर संसद पहुंचते थे।

हसरत मोहानी (1875-1951) अपने समय से बहुत आगे की सोचने वाले नेता थे। तारीख गवाह है, पूर्ण स्वराज के उनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने नौ साल बाद माना। शहीद भगत सिंह से लेकर आज तक दुनिया में कहीं भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है, तो हसरत मोहानी याद आते हैं। वह खुद ही लिखे गए हैं, *आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती/ मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं।*

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

मेहमान कलम

मानवाधिकारों और न्याय के इस युग में आज भी राजतंत्र के पुराने मुहावरे व्याप्त हैं। पुराने मुहावरे को आधुनिक लोकतंत्र के चश्मे से देखता **विवेक रंजन अग्निहोत्री** का व्यंग्य...

अंधेर नगरी चौपट राजा

रेखांकन: अवधेश राजपूत

मैं आज तक यह तय नहीं कर पाया कि राजा चौपट था इसलिए नगरी में अंधेर था या नगरी में अंधेर था, इसलिए राजा चौपट हो गया। अगर राजा चौपट था और नगरी में अंधेर नहीं था, तो वहां के नागरिकों ने बगावत क्यों नहीं की? अगर नगरी अंधेर थी और राजा चौपट नहीं था, तो राजा ने उस अंधेर को खत्म क्यों नहीं किया?

अब मूल सवाल यह है कि आज के जमाने में- जहां न्याय व्यवस्था है, मानवाधिकार हैं, विश्वव्यापी संस्थाएं हैं, भला यह मुहावरा जिंदा कैसे रह गया। आज न तो चौपट राजा संभव है, न अंधेर नगरी ...और टके सेर भाजी, टके सेर खाजा तो बिल्कुल नामुमकिन। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जिन मुहावरों के उदाहरण अब नहीं मिलते, उन्हें निरस्त कर दिया जाए? इसी असमंजस में मैं सीधे जुम्मन मियां के पास पहुंचा।

'मियां,' मैंने कहा, 'यह कैसा बेहूदा मुहावरा है। मान लिया राजा चौपट है, पर जनता तो अक्लमंद होगी। सुना है दुनिया के सबसे बड़े विज्ञानी, डाक्टर, उद्योगपति और जागरूक लोग उसी नगरी में रहते हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे बढ़िया प्रजातंत्र भी वहीं है। तो इतनी जागरूक नगरी का राजा चौपट कैसे?'

जुम्मन मियां मुस्कुराए।

'वो सब छोड़ो,' बोले, 'पहले यह बताओ, तुम इतने काबिल आदमी हो, फिर इस शहर के लोग तुम्हें वो इज्जत क्यों नहीं देते जिसके तुम हकदार हो?'

उन्होंने मेरी दुखती नस दबा दी।

'अब मैं क्या कहूं,' मैं बुदबुदाया।

'तुम्हें क्या लगता है,' जुम्मन मियां बोले, 'जो लोग कोठियों में बैठे हैं, वो तुमसे ज्यादा काबिल हैं? ये तुम्हारा शोषण करके ऊपर पहुंचे हैं और मजे की बात यह है कि ये अपने भी नहीं। बाहर से आए हैं। दीमक हैं-जो हमारा पैसा, हमारी तरक्की, हमारी संस्कृति धीरे-धीरे खा रहे हैं।'

मुझे बात सही लगने लगी।

'सोचो,' वो बोले, 'कालेज में तुम कहां थे और ये कहां। हर कोई तुम्हारा जलवा मानता था। हर लड़की तुम पर फिदा थी। ये सब दूर-दराज के गांवों से आए, हास्टल में रहे और तुम्हारे हिस्से की नौकरी, नाम और शोहरत सब खा गए।'

मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। यह सच है कि जुम्मन मियां कुछ बढ़ा-चढ़ाकर बोल रहे थे। यह भी सच है कि उन्हीं जैसे लोगों की मदद से मैं कई बार पास हुआ था, लेकिन नौकरी तो वाकई वो ले गए।

'और सुनो,' जुम्मन मियां बोले, 'अब ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी खा जाएंगे।'

'तो उपाय क्या है?' मैंने पूछा।

'हमें अपने भोपाल को फिर से महान बनाना होगा। जैसा हमारे पुरखों के जमाने में था।'

'और कैसे?'

'इन्हें यहां से निकालकर। ये हमारे दुश्मन हैं।'

'पर करेगा कौन?'

'हम करेंगे। तुम साथ दो तो। अगले नगर निगम चुनाव में हमें जिताओ। फिर देखना—जिन हाथों में ये जश्न मनाते हुए आए थे, उन्हीं हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर वापस भेजेंगे। इनकी संपत्ति पर तुम्हारा हक होगा। नौकरियां और धंधे तुम्हारे बच्चों के।'

'आप बस चुनाव में खड़े होइए,' मैंने कहा, 'हम आपको जिता देंगे।'

'ये तो शुरुआत होगी,' जुम्मन मियां बोले। 'फिर इनके जिलों से जो भी माल आएगा, उस पर टैक्स लगेगा। 50-100 नहीं, 500-1000 प्रतिशत।'

'पर उससे तो हमारा ही नुकसान होगा,' मैंने कहा। 'आलू, टमाटर, प्याज हम उगाते नहीं।'

'तो क्या हुआ?' जुम्मन मियां बोले। 'दबदबा बनेगा। महान बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। कुछ दिन टमाटर नहीं खाओगे तो क्या मर जाओगे? और अगर वो मान गए, तो सोचो—आलू- टमाटर भी आएंगे और हजार गुणा टैक्स भी।'

'और अगर उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया?'

जुम्मन मियां हंसे।

'इतने साल से मोहल्ले के गुंडों को यूं ही खिला- पिला के मोटा किया है क्या? रातों-रात भेजेंगे। उनके खेत हमारे।'

'बाकी जिले चुप रहेंगे?'

'अगर उनमें इतनी हिम्मत होती,' जुम्मन मियां बोले, 'तो भोपाल राजधानी नहीं होता। याद रखो—दुनिया ताकत के आगे झुकती है और जब ताकत गुंडागर्दी से आती है, तो दुनिया लेट जाती है।'

मुझे यकीन हो गया कि जुम्मन मियां के नेतृत्व में भोपाल को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी सामने चाय की दुकान पर दो लोगों में झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। जो कमजोर था, उसने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और मामला सुलझ गया।

जुम्मन मियां तुरंत उठे, दुकान पर गए और जोर- जोर से घोषणा करने लगे कि यह सुलह उन्होंने कराई है।

'सब लोग सुन लो,' वो बोले, 'हम यहां इसीलिए बैठे रहते हैं कि कोई झगड़ा न हो। अगर झगड़ा हो, तो हमारे पास लाओ। हम शांति करा देंगे।'

उन्होंने उस कमजोर आदमी की गिरेबान पकड़ी, उसकी तरफ़ कुछ पांच-पांच 100 के नोट बढ़ाए और ऊंची आवाज में पूछा, 'बताओ-सुलह किसने कराई?'

'मालिक आपने,' वह बोला।

'तो इस साल का शांतिदूत पुरस्कार किसे मिलना चाहिए?'

'आपको, मालिक।'

भीड़ जमा हो गई। कोई मोबाइल निकाल चुका था। जुम्मन मियां बेतुके जवाब देने लगे। खुले झूठ, बिना सिर- पैर की धमकियां। भीड़ खुश थी। तभी मुझे समझ आया कि अंधेर नगरी, चौपट राजा का असली मतलब क्या है, लेकिन फिर मुझे मुहावरे की दूसरी पंक्ति याद आई—टके सेर भाजी, टके सेर खाजा।

मतलब राजा सिर्फ चौपट नहीं था। मूर्ख भी था। या शायद नहीं। राजा न मूर्ख था, न चौपट। वह एक शातिर व्यापारी था। या यूं कहें—व्यापारी ही था। बाकी सब—मूर्खता, भ्रम, उन्माद—एक स्वांग था और प्रजातंत्र में स्वांग बिकता है, क्योंकि सच वही होता है जो सबसे जोर से खेला जाए।

(राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित फिल्मकार एवं बेस्टसेलिंग लेखक)